

प्रमाणित/प्रमाणित

दिनांक- 510 11-2/10-2004-97/2003

प्रमाणित,

महोदय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आवकारी आयुक्त,

आवकारी आयुक्त-2

प्रमाणित/दिनांक: 26 फरवरी, 2004

विषय: वर्ष 2004-05 के लिये आवकारी नीति का निर्धारण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-जी-194/एस-साइसेस-367/सुझाव आवकारी नीति/04-05 दिनांक 14 जनवरी, 2004, जी-198/एस-साइसेस-367/सुझाव आवकारी नीति/04-05 दिनांक 17 जनवरी, 2004, जी-201/एस-साइसेस-367/सुझाव आवकारी नीति/04-05 दिनांक 23 जनवरी, 2004, जी-214/एस-साइसेस-367/सुझाव आवकारी नीति/04-05 दिनांक 10 फरवरी, 2004, जी-215/एस-साइसेस-64/फुटकर भाग व्यवस्थापन नियमावली/03-04 दिनांक 10 फरवरी, 2004 एवं जी-236/एस-साइसेस-367/सुझाव आवकारी नीति/04-05 दिनांक 23 फरवरी, 2004 का संदर्भ ग्रहण करें।

इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त वर्ष 2004-05 के लिये आवकारी नीति के सम्बन्ध में अनिष्ट में लिये गये निम्नलिखित निर्णयों को सूचित करने के लिये निर्देश दिये हैं :-

1. सुझावों पर व्यवस्थापन :-

- (1) वर्ष 2004-05 के लिये आवकारी की समस्त दुकानों (दिल्ली/विदेशी मदिरा एवं बियर) का व्यवस्थापन, नियमावली में विद्यमान प्राविधानों के अनुसार नवीनीकरण/सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से किया जाएगा।
- (2) जिन दुकानों का व्यवस्थापन नवीनीकरण के माध्यम से नहीं हो पाएगा, उनका तथा नव सृजित दुकानों का व्यवस्थापन तब वर्ष 2003-04 की भांति सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से किया जाएगा, जिसके लिये भी प्रति प्राथमिक शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में रु० 1500 देय होगा।
- (3) नवीनीकरण केवल-उसी दशा में अनुमत्त होगा, जबकि अनुज्ञापी द्वारा वर्ष 2003-04 के अवधि में सभी बकायों का मुहलान कर दिया गया हो।
- (4) भाग की दुकानों का व्यवस्थापन पूर्व की भांति उत्तर प्रदेश आवकारी साइसेस (रेण्डर एवं वीलाग), नियमावली, 1991 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत नीलाग प्रणाली से कराया जाए।
- (5) जनपदवार नवीनीकरण तथा नई दुकानों के सृजन (दिल्ली/विदेशी मदिरा व बियर) का पूर्व अनुमान प्रत्येक जिला आवकारी अधिकारी से दिनांक 5.3.2004 तक प्राप्त कर

26/2/04

दिनांक- 26

सातम के पुनर्गठन आणखी अधिकार प्राप्त होकर किया जाएगा जिससे नगरपालिका के नगरपालिका स्थिति प्राप्त हो कि देशी-विदेशी मकान एवं बिचर-की-मकानों दुकानों का नवीनीकरण पद्धति से व्यवस्थापन सेवा और अवशेष विज्ञानी दुकानों (या सुविधा दुकानों को सम्मिलित करते हुए) का सामाजिक लाटरी की प्रक्रिया द्वारा व्यवस्थापन होगा।

देशी मकान-

(2.1) न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा

वर्ष 2003-04 में देशी मकान की निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा 36 प्रतिशत बी/बी के टर्म में 16.43 करोड़ बल्क लीटर में 15 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए वर्ष 2004-05 के लिये न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा 18.89 करोड़ बल्क लीटर/36 प्रतिशत बी/बी के टर्म में निर्धारित की जाती है।

दुकानों के व्यवस्थापन के प्रथम चरण में सामाजिक विज्ञापन के माध्यम से सर्वप्रथम वर्तमान अनुज्ञापियों से उनकी न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में 12 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए नवीनीकरण का विकल्प प्राप्त किया जाए।

द्वितीय चरण में अवशेष दुकानों के व्यवस्थापन के लिये 12 प्रतिशत न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा को बढ़ाते हुए लाटरी प्रक्रिया के अन्तर्गत आर्जन प्राप्त होने आए।

उक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत 18.89 करोड़ बल्क लीटर न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का व्यवस्थापन वर्तमान दुकानों के माध्यम से अवश्य होगा, अवशेष न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का व्यवस्थापन वर्तमान में सुविधा उप दुकानों तथा नई दुकानों पर किया जाए। उक्त प्रत्येक परिस्थिति में निर्धारित या यह दायित्व होगा कि वह 18.89 करोड़ बल्क लीटर न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का व्यवस्थापन माह मार्च, 2004 में करायें।

(2.2) नैसिक्त लाटरी प्रक्रिया एवं प्रोसेसिंग शुल्क -

वर्ष 2003-04 में देशी मकान की दुकानों को निर्धारित नैसिक्त लाटरी प्रोसेसिंग शुल्क वर्ष 2004-05 में भी यथावत् रहेगा।

(2.3) नवीनीकरण शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस -

देशी मकान की दुकानों की नवीनीकरण फीस के रूप में नगर निगम क्षेत्र के लिये रु० 10,000/-, नगर पालिका क्षेत्र के लिये रु० 8,000/-, नगर पंचायत क्षेत्र के लिये रु० 6,000/- तथा ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों के लिये रु० 3,000/- प्रति दुकान होगी। उक्त हेतु प्रत्येक आर्जनपत्र एवं उस पर प्रोसेसिंग फीस के रूप में रु० 1500 देय होगा।

(2.4) देशी मकान की ओगियों एवं मुख्य का निर्धारण -

वर्ष 2003-04 में प्रचलित देशी मकान की 2 क्षेत्रों- 36 प्रतिशत बी/बी व 25 प्रतिशत बी/बी, जो वर्ष 2004-05 में यथावत् रहते हुए देशी मकान की दो नई ओगियों 20 प्रतिशत बी/बी तथा 42.8 प्रतिशत बी/बी सुविधा की जाए। वर्ष 2004-05 में देशी मकान की उक्त चार ओगियों में से 25 एवं 36 प्रतिशत बी/बी की देशी मकान पर अधिकार तथा थोक/फुटकर विक्रय मुख्य वर्ष 2003-04 में अनुमोदित अधिकार एवं थोक/फुटकर विक्रय मुख्य के बराबर होगा तथा शेष दो नई ओगियों-20 व 42.8 प्रतिशत बी/बी की देशी मकान पर अधिकार एवं थोक/फुटकर विक्रय मुख्य पूर्व में अनुमोदित 36 व 25 प्रतिशत बी/बी की ओगियों की देशी मकान के लिये अनुमोदित अधिकार एवं थोक/फुटकर विक्रय मुख्य के समानाधिकार होगा।

2

(2.5) देशी मदिरा की आपूर्ति-

देशी मदिरा की आपूर्ति वर्ष 2003-04 की भांति वर्ष 2004-05 में भी सी. पी. एल.-2 के माध्यम से करायी जाएगी तथा सी. पी. एल.-2 की लाइसेंस फीस ₹50 लाख प्रति वर्ष के स्थान पर ₹20.5 लाख प्रति वर्ष होगी।

(2.6) देशी मदिरा की दुकानों की सीमा-

एक व्यक्ति को 2 से अधिक देशी मदिरा की दुकानें लेने के प्रतिबंध को 2004-05 के लिये समाप्त किया जाता है।

(2.7) दुकानों का अनुमति व्यवस्थापन -

दैनिक व्यवस्थापन के लिये 1/1000 प्रतिदिन के हिसाब से निर्धारित दैनिक लाइसेंस फीस के स्थान पर इस दुकान के लिये निर्धारित दैनिक लाइसेंस फीस का 1/365 दैनिक लाइसेंस फीस ली जाएगी।

देशी शराब की पुष्टकर दुकान की लाइसेंस फीस वर्ष के मध्य में व्यवस्थापित होने वाली देशी शराब की दैनिक लाइसेंस फीस का निर्धारण दुकान के लिये अवशेष एमोजीयस पर ही किया जाए।

(2.8) बिजली की अभाव -

आवश्यक दुकानों की समयावधि प्रातः 10 बजे से रात्रि 11 बजे तक रहेगी।

(2.9) देशी शराब की सेबुलों का अनुमोदन -

देशी शराब की सेबुलों को सेबुलों पर जैव नम्बर व निर्माण की शिथि अधिकतम कराये जाने हेतु सभी आसक्तियों की निर्देशित कर दिया जाए। इसके लिये कोई अतिरिक्त फीस नहीं ली जाएगी।

विदेशी मदिरा-

(3.1) विदेशी मदिरा की पुष्टकर बिजली के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन प्रथम विकल्प के रूप में नवीनीकरण के माध्यम से किया जाएगा। बिजली भी दुकान का नवीनीकरण उसकी वर्तमान श्रेणी से निम्न श्रेणी में नहीं किया जाएगा, जिन दुकानों का नवीनीकरण नहीं होगा अथवा नव-सज्जित दुकानों का व्यवस्थापन नियत लाइसेंस फीस पर सार्वजनिक लाइसेंस के माध्यम से किया जाएगा।

(3.2) नवीनीकरण शुल्क-

विदेशी मदिरा की दुकानों के नवीनीकरण के लिये नवीनीकरण शुल्क के रूप में वर्ष 2004-05 में नगर निगम क्षेत्र दुकानों के लिये ₹20,000/-, नगर पालिका क्षेत्र के लिये ₹14,000/-, नगर पंचायत क्षेत्र के लिये ₹10,000/- एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिये ₹3,000/- होगी। उक्त हेतु अत्यंत प्रारंभिक एवं उस पर प्रोसेसिंग फीस के रूप में ₹50,000/- देय होगा।

(3.3) लाइसेंस फीस -

वर्ष 2003-04 में विदेशी मदिरा की दुकानों के लिये निर्धारित 9 श्रेणियों में समाप्त करने के लिए नवीनीकरण की शक्ति दी जाती है। प्रतिबंध यह होगा कि जो दुकान इस वर्ष जिस श्रेणी में है, वह उसी श्रेणी में ही या उससे ऊपर की श्रेणी की लाइसेंस फीस में (बिजली के आधार पर) नवीनीकरण के लिए अनुमत्त होगी, अर्थात् यदि कोई अनुमत्त वर्तमान श्रेणी में अपनी दुकान का नवीनीकरण नहीं कराना चाहता है और उससे निम्न श्रेणी में करना चाहता है तो उसकी दुकान का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा अतः उक्त दुकान को बेटी हुई श्रेणी में सार्वजनिक

26/2/07

सादरी/आफर के माध्यम से व्यवस्थित किया जायेगा, जिसके सिधे में मरकब प्रोचोपन एवं उस पर मोसोरीन कीरा के रूप में रु० (300/-) देय होगा।

विदेशी मीरा की फुटकर गुणों की वैमिक सादरी कीरा अधिक सादरी कीरा की 1/1000 के स्थान पर 1/305 मान लीगी।

(3.4) विदेशी मीरा पर प्रतिफल शुल्क एवं मूल्य निर्धारण -

विदेशी मीरा पर प्रतिफल शुल्क निर्धारण हेतु वर्ष 2003-04 में प्रचलित मोमाल, प्रतिफल शुल्क तथा विम्व मूल्य निर्धारण सूत्र यथावत् रहेंगे, किन्तु कुछ विदेशी मीरा के साण्डो की एम.आर.पी. ऐसी हो गई है, जिस सण्ड आफ करना आवश्यक है। तब इसके सिधे विदेशी मीरा का अधिकतम फुटकर विम्व मूल्य 5 के गुणक में अगले स्तर पर आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित किया जाएगा और इस धनराशि को आबकारी सण्ड में समाहित करते हुए प्रतिफल कीरा के रूप में लिया जाएगा।

(3.5) विदेशी मीरा की आपूर्ति -

विदेशी मीरा की आपूर्ति वर्ष 2003-04 की मोति वर्ष 2004-05 में भी एम. एस.-2 के माध्यम से करायी जाएगी तथा एम.एस.-2 की सादरी कीरा रु० 1 लाख प्रति वर्ष के स्थान पर रु० 5 लाख प्रति वर्ष होगी।

(3.6) विदेशी मीरा पर आयात शुल्क -

वर्ष 2003-04 में विदेशी मीरा पर अधिरोधित आयात शुल्क रु० 2/- प्रति मोसल के स्थान पर वर्ष 2004-05 में रु० 4/- प्रति बल्क, सीटर आयात शुल्क रखा जाए।

(3.7) विदेशी मीरा की मोसल गराई शुल्क -

वर्ष 2004-05 में विदेशी मीरा की मोसल गराई शुल्क में वृद्धि करते हुए निम्नानुसार शुल्क निर्धारित किया जाए:-

क्र०	मोसल की मोती	वर्ष 2003-04 की मोसल गराई शुल्क		वर्ष 2004-05 के सिधे मोसल गराई शुल्क	
		एमएस-2 के सिधे	एमएस-3 के सिधे	एमएस-2 के सिधे	एमएस-3 के सिधे
1.	1000 मि०ली० की मोसल	1.30 रु० प्रति मोसल	1.70 रु० प्रति मोसल	2.00 रु० प्रति मोसल	2.40 रु० प्रति मोसल
2.	700 मि०ली० या 750 मि०ली० की मोसल	1.00 रु० प्रति मोसल	1.35 रु० प्रति मोसल	1.50 रु० प्रति मोसल	1.85 रु० प्रति मोसल
3.	500 मि०ली० की मोसल	0.70 रु० प्रति मोसल	1.00 रु० प्रति मोसल	1.05 रु० प्रति मोसल	1.30 रु० प्रति मोसल
4.	375 मि०ली० की मोसल	0.60 रु० प्रति मोसल	0.80 रु० प्रति मोसल	0.85 रु० प्रति मोसल	1.05 रु० प्रति मोसल
5.	180 मि०ली० की मोसल	0.40 रु० प्रति मोसल	0.50 रु० प्रति मोसल	0.55 रु० प्रति मोसल	0.65 रु० प्रति मोसल
6.	100 मि०ली० की मोसल	0.20 रु० प्रति मोसल	0.25 रु० प्रति मोसल	0.25 रु० प्रति मोसल	0.30 रु० प्रति मोसल
7.	90 मि०ली० प्रति मोसल	-	-	0.25 रु० प्रति मोसल	0.30 रु० प्रति मोसल
8.	60 मि०ली० की मोसल	0.15 रु० प्रति मोसल	0.20 रु० प्रति मोसल	0.20 रु० प्रति मोसल	0.25 रु० प्रति मोसल

26/2/04

प्रति. 5

(3.8) गुआन पर सामान शुल्क -

वर्ष 2004-05 हेतु बाइन का आयात शुल्क ₹0 2/- प्रति मोटा (750 एमएल) के स्थान पर ₹0 3/- प्रति लीटर की दर से निर्धारित किया जाएगा।

(3.9) कम सीमा के मास्क पेय पर निर्धारित शुल्क -

कम सीमा के मास्क पेय के निर्धारित शुल्क का प्राविधान नियमों में नहीं है। इसका निर्धारित अन्य प्रांतों को हो सके, इसके लिये इस पर निर्धारित शुल्क ₹0 1/- प्रति लीटर निर्धारित किया जाता है।

(3.10) अन्य प्रांतों की कम सीमा के मास्क पेय के लिये गान्ड की सुविधा -

अन्य प्रांतों में निर्मित कम सीमा के आल्कोहलिक सुवरेज के लिये गान्ड की सुविधा का प्राविधान नहीं है। प्रदेश के बाहर की अच्छी ज़ीजर की विक्री उत्तर प्रदेश में अनुमत्य करने के लिये बंदिता गोवाम का प्राविधान किया जाए तथा उक्त गान्ड की फीस ₹0 25,000 (पच्चीस हजार ₹0) वार्षिक निर्धारित की जाती है।

4. बियर(4.1) बियर की फुटकर विक्री की दुकानों का व्यवस्थापन एवं नवीनीकरण शुल्क -

बियर की फुटकर विक्री के अनुभाषनों का व्यवस्थापन प्रथम विवरण के रूप में नवीनीकरण के माध्यम से किया जाएगा। किसी भी दुकान का नवीनीकरण करने वाली श्रेणी से निम्न श्रेणी में नहीं किया जाएगा, जिन दुकानों का नवीनीकरण नहीं होगा अथवा सव-सुजित दुकानों का व्यवस्थापन नियत लाइसेंस फीस पर सार्वजनिक आदारी के माध्यम से किया जाएगा।

बियर की दुकानों के नवीनीकरण के लिये नवीनीकरण शुल्क के रूप में वर्ष 2004-05 में नगर निगम क्षेत्र दुकानों के लिये ₹0 20,000/-, नगर पालिका क्षेत्र के लिये ₹0 14,000/-, नगर पंचायत क्षेत्र के लिये ₹0 10,000/- एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिये ₹0 3,000/- होगी। उक्त हेतु प्रत्येक प्रार्थनापत्र एवं उस पर प्रोसेसिंग फीस के रूप में ₹0 1500 देय होगा।

(4.2) बियर की फुटकर दुकानों की लाइसेंस फीस -

वर्ष 2003-04 के लिये बियर की निर्धारित श्रेणियों एवं शर्तों को यथावत रखते हुए उनकी लाइसेंस फीस में 15 प्रतिशत की वृद्धि की जाती है। प्रतिबन्ध यह होगा कि जो दुकान इस वर्ष जिस श्रेणी में है, वह उसी श्रेणी में ही या उससे ऊपर की श्रेणी की लाइसेंस फीस (विक्री के आधार पर) में नवीनीकरण के लिए अनुमत्य होगी, अर्थात् यदि कोई अनुभाषी वर्तमान श्रेणी में अपनी दुकान का नवीनीकरण नहीं करना चाहता है और उससे निम्न श्रेणी में करना चाहता है तो उसकी दुकान का नवीनीकरण नहीं किया जायेगा अपितु उक्त दुकान को गरीब दुर्ग श्रेणी में लाटरी/आफर के माध्यम से व्यवस्थापित किया जायेगा, जिसके लिये प्रत्येक प्रार्थनापत्र एवं उस पर प्रोसेसिंग फीस के रूप में ₹0 1,500 लिया जाए।

बियर की फुटकर दुकानों की दैनिक लाइसेंस फीस वार्षिक लाइसेंस फीस की 1/1000 भाग के स्थान पर 1/365 भाग होगी।

१

26/2/04

5/3/04

(4.3) बियर, साइडर, पोटर, एल. एवं कम तीव्रता के मादक पेय पर आयात शुल्क एवं मुद्रा निर्धारण -

वर्ष 2003-04 में बियर पर निर्धारित अधिकार की वसुली को वर्ष 2004-05 में पर्याप्त रखा जाए तथा बियर के मुख्य वन निर्धारण पर पूर्ण की नीति बनाए रखी जाएगी।

(4.4) बियर पर निर्यात शुल्क में वृद्धि

बियर पर निर्यात शुल्क 1 अप्रैल, 1992 से मात्र 50 पैसे प्रति लीटर किया जा रहा है। बियर पर एक्सपोर्ट फीस 50 पैसे प्रति लीटर से बढ़ा कर 1.00 रुपये प्रति लीटर किया जाता है।

(4.5) बियर, पोटर, साइडर, एल. एवं कम तीव्रता के मादक पेय पर आयात शुल्क -

बियर, पोटर, साइडर, एल. एवं कम तीव्रता के मादक पेय हेतु आयात शुल्क ₹0 1/- प्रति बोतल के स्थान पर ₹0 2/- प्रति लीटर निर्धारित किया जाए तथा इसी दर पर कम तीव्रता के मादक पेय वन भी आयात करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(4.6) बियर, पोटर, साइडर, एल. एवं कम तीव्रता के मादक पेय की बोतल पर ग्राह्य शुल्क में वृद्धि किया जाता -

वर्ष 2003-04 में निर्धारित बियर की बोतल पर ग्राह्य शुल्क में 30 पैसे प्रति बोतल (650 एमएल) वृद्धि करते हुए निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:-

घोषित एमएल में	एमएल 0-3	एमएल 0-35
650 एमएल	0.55 ₹0	0.65 ₹0
350 एमएल या इससे कम	0.30 ₹0	0.40 ₹0

5. ड्राट बियर -

(5.1) ड्राट बियर पर प्रतिफल शुल्क -

वर्ष 2004-05 में माइक्रो व स्मॉल ड्राट बियर पर माइक्रो व स्मॉल बियर के समान ही प्रतिफल शुल्क लिया जाए।

(5.2) ड्राट बियर पर आयात शुल्क -

उत्तर प्रदेश में अन्य प्रांतों एवं केंद्र शासित राज्यों से आने वाली ड्राट बियर को आयात शुल्क से मुक्त रखा जाए।

(5.3) ड्राट बियर की ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन एवं लेबल अनुमोदन शुल्क में वृद्धि -

ड्राट बियर की ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन एवं लेबल अनुमोदन शुल्क से मुक्त रखा जाए तथा प्रदेश के समस्त बार अनुयायनों में ड्राट बियर की बिक्री की अनुमति प्रदान की जाती है।

(5.4) बियर, वाइन, कम तीव्रता के मादक पेय के ब्राण्ड की रजिस्ट्रेशन -

वर्ष 2004-05 में बियर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय पदार्थों पर ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस क्रमशः 10,000, 5,000 एवं 3,000 रुपये प्रति ब्राण्ड ली जाए।

2-6/2/04

6. मॉडल शाप्स
(6.1) शर्तें -

वर्ष 2004-05 के लिये निर्धारित शर्तें होगी :-

1. मॉडल शाप्स के लिये कम से कम 600 वर्ग फीट का कार्पेट परिया शेना चाहिए।
2. दुकानें व्यावसायिक रूप से स्वीकृत (कमर्शियली अप्रूव्ड परिया) मात्र ही खोली जाएगी।
3. दुकान में रूपायलेट की व्यवस्था अनिवार्य होगी।
4. दुकान पूर्णतया वातायुधूलित होगी।

मॉडल शाप्स के अनुदानों को अगले 5 वर्षों तक शासन द्वारा पूर्व निर्धारित शर्तों पर नवीनीकृत किया जा सकता है।

(6.2) लाइसेंस फीस

वर्ष 2004-05 में महानगरी में खुलने वाली मॉडल शाप्स के लिये निर्धारित लाइसेंस फीस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, किन्तु अन्य नगरों में भी मॉडल शाप्स खुले, इसके लिये अन्य नगरों की मॉडल शाप्स की लाइसेंस फीस रु 10 लाख के स्थान पर रु 8 लाख वार्षिक रखी जाए। साथ ही राजस्व की दृष्टिकोण से यह प्रतिबन्ध लगाया जाए कि अन्य नगरों के लिये निर्धारित लाइसेंस फीस को रु 8 लाख वार्षिक अथवा उचित नियंत्रण क्षेत्र में विदेशी मदिरा की सबसे अधिक लाइसेंस फीस और बिस्तर की दुकान की सबसे अधिक लाइसेंस फीस को जोड़कर, जो भी अधिक हो, वही धनराशि उचित जनपद में खुलने वाली मॉडल शाप्स की लाइसेंस फीस होगी। उदाहरण के लिये किसी छोटे नगर में विदेशी मदिरा की अधिकतम लाइसेंस फीस 12 लाख और बिस्तर की अधिकतम लाइसेंस फीस 2 लाख है, तो उस नगर के लिये मॉडल शाप्स की लाइसेंस फीस 8 लाख न होकर 14 लाख होगी। वर्ष 2004-05 में मॉडल शाप्स पर विदेशी मदिरा, बिस्तर, नाइल व कम तीव्रता के माइक पेय के पिलाने की भी सखिया होगी, जिसके लिये रु 50,000 आंतरिकता लाइसेंस फीस देय होगी। आवश्यकता आनुवत यह सुनिश्चित करेंगे कि वर्ष 2004-05 में कम से कम 150 नई मॉडल शाप्स खुले, इसके लिये जनपदवार लक्ष्य निर्धारित किया जाए।

(6.3) नवीनीकरण

प्रदेश में इस वर्ष कुल 17 मॉडल शाप्स अगले वर्ष 2004-05 के लिये नवीनीकृत कर दी जाएं तथा इसके लिये नवीनीकरण शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस के रूप में रु 25,000/- लिये जाएं।

7. राज के मध्य में नई दुकानें खोलने का प्राधिकार :-

आजकरी आयुक्त को यह अधिकार होगा कि वह आवश्यकतानुसार राज के मध्य में देशी/विदेशी मदिरा व बिस्तर की फुटकर बिक्री की दुकानों की निर्धारित संख्या का 10 प्रतिशत तक नई दुकानें खोल सकेंगे। 10 प्रतिशत से अधिक दुकानें खोलने के लिये आजकरी आयुक्त द्वारा शासन से अनुमोदन प्राप्त किया जाए। मॉडल शाप्स की दुकानें खोलने की प्रक्रिया अर्ध-वर्षा चलेगी।

26/2/04

6 अक्टूबर 8

४. आय आदेश -

(४.१) निर्धारित परमिट फीस -

- ०१ अप्रैल, २००४ से विद्युत अल्कोहल एवं पावर अल्कोहल पर निर्धारित फीस १.०० रु० प्रति लीटर कर दी जाएगी।
- वर्ष २००४-०५ में रेडिफाइड रिफर एवं ई०एन०ए० पर निर्धारित परमिट फीस निम्नानुसार निर्धारित की जाएगी :-

रेडिफाइड रिफर	२.५० रुपये प्रति लीटर
एक्सल्यूट अल्कोहल/ई०एन०ए०	३.०० रुपये प्रति लीटर

(४.२) अल्कोहल पर आयदा परमिट फीस -

अल्कोहल पर आयदा परमिट फीस लिये जाने का प्राविधान अभी तक नियमों में नहीं है। अतः नियमों में अल्कोहल आयदा का प्राविधान करके उत्तर प्रदेश में आयदा परमिट फीस रु० १.५० प्रति लीटर निर्धारित की जाती है।

(४.३) परचोन टैक्स -

परचोन टैक्स की प्रचलित २ श्रेणियों को समाप्त करके केवल एक ही श्रेणी ०.०० पैसे प्रति लीटर निर्धारित किया जाता है।

(४.४) डिनेचुरेशन फीस -

नियमों में उत्तर प्रदेश में ए०ए०एल०-१६, १७, ३९, ४० तथा ४१ अनुसूचियों पर निशान की जाने वाली सिस्ट पर १० पैसे प्रति लीटर की दर से डिनेचुरेशन फीस लिये जाने का प्राविधान किया गया है, जिसके अन्तर्गत निर्यात की जाने वाली विद्युत भुस (जिसमें पावर अल्कोहल भी सम्मिलित है) सम्मिलित नहीं है। इस कारण इस पर डिनेचुरेशन फीस प्राप्त नहीं हो रही है। नियमावली में संशोधन करके सभी प्रकार की विद्युत सिस्ट पर १५ पैसे प्रति लीटर डिनेचुरेशन फीस ली जाएगी।

(४.५) नार लाइसेंस फीस में वृद्धि -

वर्ष २००४-०५ में सभी श्रेणी की नार लाइसेंस फीस में समान रूप से रु० २५,०००/- की वृद्धि की जाती है।

(४.६) वन्यायीन गोदाम -

बी०डब्ल्यू०ए०एल०-२ए (विदेशी मांवेरा), बी०डब्ल्यू०ए०एल०-२बी (मिसर, साइडर, पोटर, एल.) तथा बी०डब्ल्यू०ए०एल०-२सी (साइन) के लिये निर्धारित वार्षिक लाइसेंस फीस यथावत् रखी जाए तथा कम सीकरा के मादक पेय के लिये एक नये वन्यायीन गोदाम- बी०डब्ल्यू०ए०एल०-२डी के शुचित किया जाए, जिसकी वार्षिक लाइसेंस फीस रु० ०.२५ लाख वार्षिक होगी। इन बाण्ड अनुसूचियों की प्रविशुति चरदाशि में निम्नानुसार बढ़ोतरी की जाती है :-

क्रमांक	अनुसूचन का नाम	वर्तमान	वर्ष २००४-०५ के लिये निर्धारित
१.	बी०डब्ल्यू०ए०एल०-२ए	रु० १.०० लाख	रु० ३.०० लाख
२.	बी०डब्ल्यू०ए०एल०-२बी	रु० ०.१५ लाख	रु० १.०० लाख
३.	बी०डब्ल्यू०ए०एल०-२सी	रु० ०.१५ लाख	रु० ०.२५ लाख
४.	बी०डब्ल्यू०ए०एल०-२डी	-	रु० ०.१५ लाख

26/2/04

- 9 -

(8.7) समुपकार की आपूर्ति विदेशी मदिरा-

वर्ष 2003-04 में समुपकार की आपूर्ति विवर पर अभिलेखित आगत परीमेटर कीमत रु 50/- प्रति बोतल (650 एमएल) में कमी करते हुए वर्ष 2004-05 के लिये दरों विवर के लिये रु 25/- प्रति बोतल तथा माहल विवर पर रु 20/- प्रति बोतल निर्धारित की जाती है।

(8.8) लाइसी व अन्य नवीं पुनर्गनों का व्यवस्थापन एवं अभिकर्त-

इन दोनों प्रकार की पुनर्गनों के व्यवस्थापन की प्रक्रिया, रेगुलेशन एवं अभिकर्त प्रभावित रहेगा।

(8.9) उपरोक्त विभागों के आंतरिक शेष प्राविधान एवं प्रक्रिया पूर्ववत् रहेगी।

9. वर्ष 2004-05 में आवश्यकरी राज्य का लक्ष्य :-

वर्ष 2004-05 के लिये राज्य प्राप्ति के सम्बन्ध में आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अनुमान एवं शासन स्तर पर हुई अनेक बैठकों में विचार-विमर्श के उपरान्त निम्नानुसार लक्ष्य प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया था :-

1.	देशी शराब की लाइसेंस फीस + प्रतिफल फीस	1600 करोड़ रुपये
2.	विदेशी मदिरा की लाइसेंस फीस + प्रतिफल फीस (माहल शाप सहित)	1000 करोड़ रुपये
3.	विषय की लाइसेंस फीस + प्रतिफल फीस	150 करोड़ रुपये
4.	अन्य प्राप्ति	250 करोड़ रुपये
	योग	2000 करोड़ रुपये

उपरोक्त अनुमानित लक्ष्य में 120 करोड़ रु की वृद्धि की जाती है। अर्थात् 2004-05 में आवश्यकरी राज्य के लक्ष्य के रूप में रु 2000 करोड़ निर्धारित किया जाता है। आवश्यकरी आयुक्त को यह दिश निवेदित जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राज्य प्राप्ति के अधिकतम में रु 120 करोड़ की वृद्धि अर्थात् कुल रु 2000 करोड़ की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिये अभी से पुनः मद्रास राज्य निर्धारित करते हुए स्पष्ट कार्य योजना बनाकर शासन को 15 मार्च, 2004 तक प्रस्तुत किया जाए।

10. प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने हेतु आवश्यकरी विभाग द्वारा निर्गमित रूप से प्रवर्तन की प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। आवश्यकरी आयुक्त द्वारा दिनांक 21 मार्च, 2003 के पूर्व जनपदवार/खुसमवार/माहवार वर्ष 2004-05 में लाइसेंस फीस एवं सिविलीरिटी के रूप में अनुमानित धनराशि तथा उसके सापेक्ष प्राप्त होने वाली धनराशि का विवरण उपलब्ध कराया जाए। इस पर में प्राप्ति का सत्यापन ट्रेजरी से कराया जाए।

11. मदिरा की तस्करी एवं अवैध मद्य-निष्कर्षण को रोकने हेतु आवश्यकरी आयुक्त द्वारा वर्ष 2003-04 में विशेष प्रयास किया जाए तथा इस हेतु स्थापित 29 चेक पोस्टों एवं 10 सबल बस्तों तथा जनपदों में तैनात प्रवर्तन स्टाफ की विशेष रूप से सक्रिय किया जाए। फलस्वरूप अभियोगों की मासिक समीक्षा कर उसकी रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करायी जाए।

26/4/04

दिनांक: 16

10

12. उपरोक्तानुसार कार्योन्मूलन सुनिश्चित करने हेतु निम्न नियमों/अधिसूचनाओं में संशोधन/परिवर्तन/आपमार्जन की कार्यवाही अपनाये गये नियम/नियमावलीयों तथा अधिसूचनाओं का प्रकाशन किया जाना हो, उनका समय स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने 31 मार्च, 2004 से पूर्व प्रकाशन कराना जाना प्रत्येक वर्ष में सुनिश्चित किया जाए। निम्न नियमों/अधिसूचनाओं का प्रकाशन शरान स्तर से किया जाना है, उनका प्रस्ताव नियमित प्रारूप पर एक सप्ताह के अन्दर अपनाय उपलब्ध करा दिया जाए, ताकि समय से आपाणी कार्यवाही की जा सके।

प्रमुख-सेवा एकाग्र/दिना /

प्रमुख,

2.6.2004

(अधीन नियम)

2/